



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 19 फरवरी, 2007/30 माघ, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 फरवरी, 2007

संख्या एल०एल०आर०-डी(६)-३६/२००६-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18-02-2007 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 31) को

वर्ष 2007 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2006

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. परिभाषाएं ।
3. बलपूर्वक संपरिवर्तन का प्रतिषेध ।
4. आशय की सूचना ।
5. धारा 3 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड ।
6. अपराध का संज्ञेय होना ।
7. अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से होगा ।
8. नियम बनाने की शक्ति ।

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2006

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 18 फरवरी, 2007 को यथा अनुमोदित)

किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में बल प्रयोग या उत्प्रेरणा द्वारा या कपटपूर्ण साधनों द्वारा संपरिवर्तन प्रतिषिद्ध करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- | | |
|-----------------|---|
| संक्षिप्त नाम । | 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2006 है । |
| परिभाषाएं । | <p>2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—</p> <p>(क) “संपरिवर्तन” से एक धर्म का त्याग करना तथा दूसरे को अपनाना अभिप्रेत है;</p> <p>(ख) “बल” के अन्तर्गत बल का प्रदर्शन या क्षति की धमकी या देवी अप्रसाद या सामाजिक बहिष्कार की धमकी आएगी;</p> <p>(ग) “कपट” के अन्तर्गत दुर्यपदेशन या अन्य कपटपूर्ण प्रयुक्ति आएगी;</p> <p>(घ) “उत्प्रेरणा” के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के दान या परितोषण की, या तो वस्तुरूप में या नकद में प्रस्थापना करना या किसी भी प्रकार की प्रसुविधा, चाहे धन सम्बन्धी हो या अन्यथा, देना आएगा; और</p> <p>(ङ) “अव्यस्क” से अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अभिप्रेत है ।</p> |

3. कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्षतः या अन्यथा किसी भी व्यक्ति को, बल प्रयोग द्वारा या उत्प्रेरणा द्वारा या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन द्वारा किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में न तो संपरिवर्तित करेगा न ही इसका प्रयत्न करेगा न ही कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी संपरिवर्तन को दुष्प्रेरित करेगा :

बलपूर्वक संपरिवर्तन का प्रतिषेध ।

परन्तु कोई भी व्यक्ति जिसका इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी एक धर्म से दूसरे में संपरिवर्तन हुआ है तो वह संपरिवर्तित हुआ नहीं समझा जाएगा ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी एक धर्म से दूसरे में संपरिवर्तन का आशय रखता है तो वह अपने ऐसा करने के आशय की कम से कम तीस दिन की पूर्विक सूचना सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट को देगा और जिला मजिस्ट्रेट मामले की जांच, ऐसे अभिकरण, जैसा वह उचित समझे, से करवाएगा:

आशय की सूचना ।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापिस आना चाहता है तो कोई सूचना अपेक्षित नहीं होगी ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित पूर्विक सूचना देने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

5. कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह, किसी भी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा :

धारा 3 के उल्लंघन के लिए दण्ड ।

परन्तु यदि अपराध किसी अव्यस्क, किसी महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की बाबत किया गया है तो कारावास का दण्ड तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा ।

6. इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होगा तथा इसका अन्वेषण अपराध का संज्ञेय होना । पुलिस निरीक्षक से नीचे की पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा ।

अभियोजन
जिला
मजिस्ट्रेट की
मंजूरी से
होगा।

7. इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अभियोजन, जिला मजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो उपमण्डल अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे उस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किया जाए, की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

नियम बनाने
की शक्ति।

8. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION
ACT, 2006**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections :

1. Short title.
2. Definitions.
3. Prohibition of forcible conversion.
4. Notice of intention.
5. Punishment for contravention of the provisions of section 3.
6. Offence to be cognizable.
7. Prosecution to be made with the sanction of District Magistrate.
8. Power to make rules.

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION ACT, 2006

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 18TH FEBRUARY, 2007)

AN

ACT

to provide for prohibition of conversion from one religion to another by the use of force or inducement or by fraudulent means and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2006.

Definitions. 2. In this Act, unless the context otherwise requires—

- (a) “conversion” means renouncing one religion and adopting another;
- (b) “force” shall include show of force or threat of injury or threat of divine displeasure or social ex-communication;
- (c) “fraud” shall include misrepresentation or any other fraudulent contrivance;
- (d) “inducement” shall include the offer of any gift or gratification, either in cash or in kind or grant of any benefit either pecuniary or otherwise; and
- (e) “minor” means a person under eighteen years of age.

Prohibition of forcible conversion. 3. No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any person from one religion to another by the use of force or by inducement or by any other fraudulent means nor shall any person abet any such conversion :

Provided that any person who has been converted from one religion to another, in contravention of the provisions of this section, shall be deemed not to have been converted.

4. (1) A person intending to convert from one religion to another shall give prior notice of at least thirty days to the District Magistrate of the district concerned of his intention to do so and the District Magistrate shall get the matter enquired into by such agency as he may deem fit: Notice of intention.

Provided that no notice shall be required if a person reverts back to his original religion.

(2) Any person who fails to give prior notice, as required under sub-section (1), shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

5. Any person contravening the provisions contained in section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punishable with imprisonment of either description which may extend to two years or with fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both : Punishment for contravention of the provision of section 3.

Provided that in case the offence is committed in respect of a minor, a woman or a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, the punishment of imprisonment may extend to three years and fine may extend to fifty thousand rupees.

6. An offence under this Act shall be cognizable and shall not be investigated by an officer below the rank of an Inspector of Police. Offence to be cognizable.

7. No prosecution for an offence under this Act shall be made without the sanction of the District Magistrate or such other authority, not below the rank of a Sub-Divisional Officer, as may be authorized by him in that behalf. Prosecution to be made with the sanction of District Magistrate.

8. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act. Power to make rules.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before expiry of the session in which it is so

laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rules should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.